

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं० 2018/00214 (102/2018)

महंगासिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति बावरी निवासी 8 एम.के.एस. तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़। — अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

— रेस्पोंडेंट



अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 03.04.2018
प्रकरण संख्या 17/2018 बअनवानी महंगासिंह बनाम तहसीलदार

श्री राजेश दीपराय, अधिवक्ता अपीलान्त।

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक - 22.02.21


1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि चक 8 एम.के.एस. में 26 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। इसके खातेदारी व नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है। कृषि भूमि के पेटे राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक राशि जमा करवाने को तैयार है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रार्थी की काश्तशुदा फसल के समय प्रार्थी क फसल को नीलाम [redacted] के आदेश

leao

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रदान किये हैं जबकि तहसीलदार को फसल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने खातेदारी/नियमन की पत्रावली का हस्तान्तरण जब तक नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी तहसीलदार को प्रश्नगत कृषि नीलाम करने से निषेध करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रार्थना-पत्र को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट की फसल काशत है। रेस्पोंडेंट अपीलान्ट की फसल को नीलाम करने को कटिबद्ध है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट से इस संबंध में कोई जवाबदेही लिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होने की विवेचना करते हुए स्थगन प्रार्थना-पत्र खारिज करने के आदेश दिये हैं लेकिन प्रथम दृष्टया मामला किसी प्रकार से नहीं बनता है इस संबंध में कोई विवेचना नहीं किया तथ न ही सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू के संबंध में कोई विवेचना नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
4. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकूलाय की बहस पर मनन किया।
5. अपीलान्ट ने चक 8 एम.के.एस. में 26 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। इसके खातेदारी व नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है। कृषि भूमि के पेटे राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक राशि जमा करवाने को तैयार है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रार्थी की काशतशुदा फसल के समय प्रार्थी क फसल को नीलाम करने के आदेश प्रदान किये हैं। जिससे बचाव हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने स्थगन प्रार्थना-पत्र


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़





प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय के मतानुसार अपीलान्ट का कब्जा साधिकार नहीं है तथा खातेदारी/नियमन की कार्यवाही विचाराधीन होने के प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 22.2.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

22/2/21
 (करतारसिंह पूनीया)
 आर.ए.एस. राजस्व अपील प्राधिकारी
 राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
 हनुमानगढ़